साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 25-31 मार्च 2024 वर्ष-9, अंक-49

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

आएंगे अच्छे दिनः सहकारी एजेंसियां बढ़ाएंगी किसानों की आय

अगले पांच साल में हर जिले में स्थापित होगी जैविक फॉर्म-लैब

ऑर्गेनिक उत्पादों का 70 हजार करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य तय

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन नई सहकारी समितियां को मैदान में उतार दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि नई सहकारी समितियां एनसीओएल, एनसीईएल और बीबीएसएसएल किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम करेंगी।

यह तीनों समितियां किसानों की फसल की बिक्री, निर्यात, कृषि समस्याओं, जरूरतों को पूरा करेंगी। किसानों को लिए फायदेमंद कृषि इकोसिस्टम विकसित करेंगी। सरकार ने ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रूपए पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं, जैविक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अगले 5 साल में हर जिले में जैविक फॉर्म और लैब स्थापित करेगी।

70 हजार करोड़ का ऑर्गेनिक निर्यात लक्ष्य

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र ने ऑर्गेनिक खेती से उपजे उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने का टारगेट तय किया है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत के मौजूदा ऑर्गेनिक निर्यात को 7 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70 हजार करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। तीनों सहकारी समतियां जैविक खाद पदार्थों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने का लक्ष्य तय किया है।

रासायनिक उर्वरक उपयोग घटाने पर जोर

सहकारिता मंत्रालय के अनुसार तीन नई सहकारी समितियां एनसीओएल, एनसीईएल और बीबीएसएसएल भारतीय कृषि की कई समस्याओं को हल करने में मदद करेंगी और जैविक खाद्य पदार्थों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाएंगी। सरकार ने फसलों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को घटाने पर जोर दिया है और जैविक-प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में हर जिले में जैविक फार्म और उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित होगी।

तीनों समितियों के काम बंटे

एनसीओएल देश में जैविक खेती को बढ़ावा देगी, जो पहले ही बाजार में कई जैविक उत्पाद पेश कर चुकी है। कुल वैश्विक जैविक बाजार 10 लाख करोड़ रुपए का है और भारत का जैविक उत्पादों का निर्यात केवल 7,000 करोड़ रुपए है। सहकारिता मंत्रालय भारत के जैविक निर्यात को 70,000 करोड़ तक बढ़ाने पर काम कर रहा है। वहीं, सहकारी समिति बीज सोसायटी बीबीएसएसएल के लिए उन्होंने कहा कि लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। जबकि, एनसीईएल का गठन सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

बर्ड फ्लू, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, रेबीज जैसी बीमारियों की होगी जांच

पशुओं की जांच के लिए भोपाल में शुरू होगी प्रदेश की दूसरी बड़ी लैब

राज्य पशु चिकित्सालय परिसर में लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू

निर्माण कार्य पूरा होने और उपकरणों की खरीदी के बाद शुरू होगी जांच

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुओं की बीमारियों की जांच के लिए भोपाल में प्रदेश की दूसरी बड़ी लैब शुरू होगी। राज्य पशु चिकित्सालय परिसर में लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस लैब में बर्ड फ्लू, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, रेबीज जैसी संक्रामक और खतरनाक बीमारियों की जांच हो सकेगी। अभी भोपाल के आनंद नगर में केंद्र सरकार की हाई सिक्यूरिटी एनिमल डिजीज लैब है जहां इन बीमारियों की जांच होती है। यहां भारत ही नहीं पूरे एशिया से सैंपल आते हैं। इस कारण जांच में अधिक समय लगता है। नई लैब सुरक्षा के मापदंड से बायोलाजिकल सेफ्टी लेवल (बीएसएल) 2 प्लस स्तर की होगी, जबकि केंद्र सरकार की लैब बीएसएल तीन स्तर की है।

एक करोड़ रुपए की लागत आएगी

राज्य पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला के अधिकारियों ने बताया कि दो वर्ष पहले ही यहां की लैब को उन्नत कर बीएसल 2 स्तर का बनाया गया था। अब फिर इसे उन्नत बनाया जा रहा है। इसमें एक करोड़ रुपए की लागत आएगी। लैब के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। निर्माण कार्य पूरा होने और उपकरणों की खरीदी के बाद जांचें शुरू हो जाएंगी। इसमें लगभग छह माह लगेंगे।

पशुपालकों को मिलेगा लाभ

यह लैब बनने का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। बर्ड फ्लू समेत पशुओं में होने वाली कई ऐसी बीमारियां इंसानों में भी आ सकती हैं। ऐसे में इनकी समय पर जांच, उपचार और रोकथाम आवश्यक होता है। पिछले दो वर्ष से लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) के मामले भी प्रदेश समेत देशभर में बढ़े हैं। इसकी जांच के लिए अभी सैंपल हाई सिक्यूरिटी एनिमल डिजीज लैब में भेजे जा रहे हैं। राज्य सरकार की लैब उन्नत होने के बाद यहां पर एलएसडी की जांच भी हो सकेगी। साथ ही लैब बनने से बीमारियों पर शोध भी किया जा सकेगा।

कृषि की तर्ज पर अब पशुपालन के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, दूध उत्पादन बढ़ाने में मिलेगी मदद

देश में अब एआई से होगी पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही इसके उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में एआई से बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसका फायदा भी दिखाई दे रहा है। कृषि की तर्ज पर अब पशुपालन के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए पशुओं के स्वास्थ्य का पता लगाना आसन हो जाएगा। पशुओं के स्वास्थ्य का पता लगाता चुनौतीपूर्ण होता है। पशु अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। इसके कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। पर अब एआई तकनीक से इस्तेमाल से इसे आसान बनाया जा रहा है और किसानों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। पशुपालन में एआई का इस्तेमाल करते हुए इसमें दूर से ही पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्राप्त आंकड़े को कंप्यूटर से देखा जाता है। इससे बीमार पशुओं के असमान्य व्यवहार का पता चलता है। इतना ही नहीं, इसके जरिए दूध उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

किसानों की बढ़ेगी आय

दूध उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। एक फैक्ट यह भी है कि भारत में किसानों और उनके परिवारों की कमाई कृषि की सफलता पर निर्भर करती है। देश में कई ऐसे स्टार्टअप्स और निजी संस्थाएं हैं जो देश के किसानों को बेहतर पैदावार के लिए तकनीकी सेवाएं और सलाह मुहैया कराते हैं। इन स्टार्टअप्स के जरिए देश में खेती और पशुपालन का तरीका बदल रहा है।

पशुपालन में एआई के फायदे

एआई के जरिए पशुपालन में मदद मिल सकती है, क्योंकि इससे पशुओं के बारे में सभी प्रकार की जानकारी हासिल की जा सकती है। साथ ही, उनके खान-पान और मौसम संबंधी बदलाव, बदलते मौसम में उनके व्यवहार में बदलाव, रोग होने पर लक्षण और उससे संबंधित डाटा आसानी से हासिल किया जा सकता है। इससे उनके रख-रखाव में आसानी हो सकती है। साथ ही उनके खान पान के बारे में बेहतर डाटा हासिल करके उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। उनके गर्भाधान को और बेहतर बनाया जा सकता है। इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, जिससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हासिल की जा सकती है।

एआई की चुनौतियां

हालांकि एआई के जहां एक तरफ फायदे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसकी चुनौतियां भी हैं। अधिकांश लोग यह नहीं समझते हैं कि एआई क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खास कर गैर तकनीकी क्षेत्र के लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। यही कारण है कि कृषि के क्षेत्र में इसे अपनाने में देरी हो रही है। देश के पारंपरिक किसानों को इसे समझने में परेशानी हो रही है, क्योंकि पारंपरिक किसान नई तकनीकों से दूर रहते हैं। इसलिए समझने में उन्हें समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा एक और समस्या एआई को अपनाने में होने वाले निवेश की है। शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल करना महंगा साबित हो सकता है। इसके लिए अधिक पूंजी लगती है। इसलिए इसे अपनाने में एक समय लग सकता है।

» आर्गेनिक फार्मिंग, एक लाख से ज्यादा पौधों का रोपण

» पेड़ों को पानी देने के लिए जंगल के बीच बनाया तालाब

तीन साल में बंजर पहाड़ी को बना दिया हरा-भरा जंगल

› भावसिंगपुरा के 200 से अधिक लोगों को मिल रहा रोजगार

› जंगल की देखरेख के लिए हैदराबाद की नर्सरी को दिया काम

खंडवा। जागत गांव हमार

मन में कुछ करने की चाह हो तो सबकुछ मुमकिन हो सकता है। ऐसा ही कुछ शहर के एक व्यापारी ने भी अपनी दृढ़ निष्ठा से कर दिखाया है। व्यापारी ने पर्यावरण संरक्षण की ओर एक कदम बढ़ाया। जिसमें उसने 80 एकड़ की बंजर और पथरीली पहाड़ी को तीन साल की मेहनत में हरा-भरा कर दिया। हरसूद रोड पर भावसिंगपुरा गांव के पास ये जंगल अब विशाल रुप धारण करने लगा है और एक से दो किमी दूर से भी आसानी से नजर आने लगा है। व्यापारी ने इस पहाड़ी पर आर्गेनिक फार्मिंग शुरु की है। जिसके तहत यहां लगभग एक लाख से अधिक पौधे लगाए गए है। जिनमें से अधिकतर अब बड़े होकर लहलहा रहे हैं। जंगल की देखरेख का काम हैदराबाद की एक कंपनी को दिया गया है। जिसे आर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में खासा अनुभव है। व्यापारी की इस पहल से रुधी, भावसिंगपुरा व अमलपुरा सहित आसपास के कुछ गांव के 200 से अधिक लोगों को यहां रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। 80 एकड़ की पहाड़ी पर ये आर्गेनिक फार्मिंग शहर के व्यापारी राकेश बंसल के द्वारा की जा रही है। इस कार्य में उनके परिवार के नगीनचंद बंसल, अनुराग बंसल, आशुतोष बंसल व अनिकेत बंसल भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं।

ऐसे आया जंगल बनाने का आइडिया

व्यापारी राकेश बंसल ने बताया कि कोविड के समय सबकुछ बंद हो चुका था। इस दौरान देखने में आया कि आक्सीजन की कितनी आवश्यकता है। पूरी देश में आक्सीजन के लिए मारा-मारी देखने को मिली। तब ही मेरा मिलना कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे थे। आर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से उन्होंने बड़े-बड़े जंगल तैयार किए। उनके हरे-भरे जंगलों को देख आइडिया आया कि खंडवा में भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह पहल की जा सकती है।

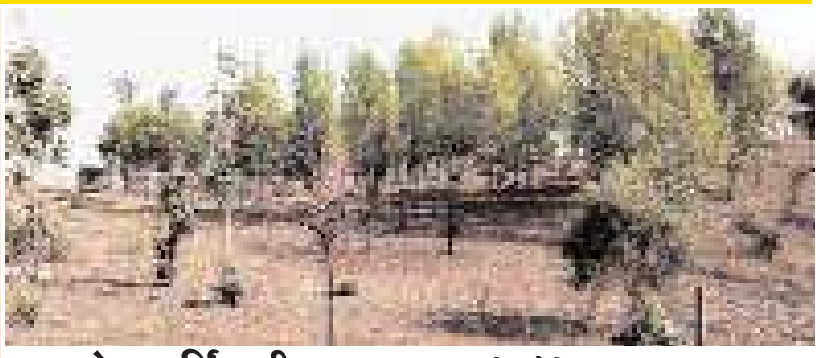

स्टेप फार्मिंग की तर्ज पर काम

बंसल ने बताया कि भावसिंग पुरा में मेरे पास काफी जमीन थी। जो पूरी तरह बंजर पड़ी हुई थी। इस पत्थीरी और बंजर पहाड़ी को कुछ हद तक समतल किया। इसके बाद यहां आसाम की स्टेप फार्मिंग की तर्ज पर पौधे लगाने का काम शुरु किया गया। बंजर पहाड़ी को पौधे लगाने लायक बनाने में लगभग एक साल का समय लग गया।

15 प्रकार के पौधे

पहाड़ी पर लगे हैं 12 से 15 प्रकार के पौधे पहाड़ी पर लगभग 12 से 15 प्रकार के पेड़-पौधे लगे हुए है। जिनमें विशेष रुप से केसर, आम और महोगनी के पौधे लगे हुए है। इसके अलावा यहां बांस, जाम, चैरी, जामुन, सेहतु, नारियल, चीकू, वाटर एप्पल, ड्रेगन फ्रूट, अनार आदि के पौधे लगे हुए हैं।

ड्रिप एरिगेशन

यहां सबसे खास बात ये है कि किसी भी पौधे पर किसी प्रकार का कोई रसायनिक खाद या उर्वरक उपयोग नहीं किया जाता है। नगीनचंद बंसल ने बताया कि यहां गाय के गोबर, छाछ, गुड़ व अन्य प्रकार के पदार्थों को मिलाकर लिक्विड खाद बनाया जाता है। जिसे गौ कृपा अमृतम कहा जाता है। जिसे ड्रिप एरिगेशन के माध्यम से पौधों में डाला जाता है।

गहरे तालाब का निर्माण

एक करोड़ लीटर पानी की क्षमता का तालाब जंगल में पेड़-पौधों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था के लिए यहां एक ऊंचाई वाले स्थान पर 70 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरे तालाब का निर्माण किया गया है। इसमें लगभग एक करोड़ लीटर जलभराव की क्षमता है। इस तालाब से जंगल की सिंचाई में काफी फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही यहां दो गोशालाएं भी बनाई गई है। जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पशुओं को रखा गया है।

आर्गेनिक फार्मिंग के फायदे

आर्गेनिक फार्मिंग के एक्सपर्ट रहमान अंसारी और शेख जिलानी (जैद नर्सरी) ने बताया कि आर्गेनिक फार्मिंग पूरी तरह केमिकल फ्री होती है। पेड़-पौधों को इससे अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं। इन पेड़ों में लगने वाले फलों को खाने से कई तरह रोगों से मुक्ति मिलती है। खासकर पेट की समस्याओं से व्यक्ति को निजात मिलती है। इससे जमीन को भी खासा फायदा होता है। भूमि की पकड़ और उर्वरक क्षमता बरकार रहती है। इसमें पनपने वाला चारा भी काफी पौष्टिक होता है जो पशुओं के लिए काफी फायदेमंद होता है।

बी-फार्मिंग भी साथ में हो रही

इसी जंगल में मधुमक्खियों का भी आशियाना बना हुआ है। अनिकेत बंसल ने बताया कि जंगल में बड़े लेवल पर बी-फार्मिंग भी की जा रही है। यहां लगभग 50 से ज्यादा बी-हाइव बाक्स लगे हुए है। एक बाक्स में लगभग 10 से 20 हजार मधुमक्खियां रहती है। इनसे शहद मिलने के साथ ही जंगल के पेड़ों को भी फायदा मिलता है। पेड़ों पर जब फल पनपने लगते हैं तो ये मधुमक्खियां इन फलों की क्वालिटी इंप्रूव करती है। इनसे फल की डेंसिटी भी बढ़ती है,उत्पादन बढ़ता है।

बफर खरीद मूल्य पर दाल की सरकारी खरीद की प्रक्रिया जनवरी से शुरू

सरकार ई-समृद्धि पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों से 6 लाख टन दाल खरीदेगी

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ई-समृद्धि पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों से सीधे दाल खरीदने का निर्णय लिया है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार बफर स्टॉक के लिए किसानों से 6 लाख टन दाल की खरीद की जाएगी। खरीद प्रक्रिया को सहकारी समिति नाफेड और एनसीसीएफ के जरिए पूरा किया जाएगा। बफर खरीद मूल्य पर दाल की सरकारी खरीद की प्रक्रिया जनवरी से चल रही है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सीधे उनसे अरहर और मसूर दाल की खरीद की जाएगी। बफर स्टॉक के लिए सहकारी समितियों नाफेड और एनसीसीएफ ई-समृद्धि पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों से 6 लाख टन दाल की खरीद कर रही हैं। इसमें 4 लाख टन अरहर की दाल खरीदी जाएगी और 2 लाख टन मसूर की दाल खरीदी जाएगी। सरकार बाजार में दाल आपूर्ति बनाए रखे के लिए बफर स्टॉक के लिए किसानों से दाल खरीद कर रही है। जबकि, सालाना खपत पूरी करने के सरकार दालों का आयात भी करती है।

8 हजार टन अरहर खरीदी - अरहर दाल की खरीद जनवरी महीने में किसानों से शुरू की जा चुकी है, जबकि मसूर दाल की खरीद मार्च में शुरू की गई है। अब तक नेफेड और एनसीसीएफ ने 8 हजार टन अरहर दाल की खरीद कर ली है। दोनों दालों की खरीद प्रक्रिया जारी है। इस रबी सीजन के लिए दालों की सरकारी खरीद 1 महीने पहले ही शुरू कर दी गई है। आमतौर पर अप्रैल में शुरू होने वाली सरकारी खरीद मार्च में और जनवरी में ही शुरू कर दी गई है।

बफर मूल्य पर दाल खरीदी

किसानों से खरीदी जाने वाली दाल की कीमत खरीद न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य या बफर खरीद मूल्य के हिसाब से मिलेगी। सरकार ने 2023-24 में अरहर यानी तूर दाल की खरीद का मूल्य 7000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो बीते 2022-23 सीजन की तुलना में 400 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। वहीं, मसूर दाल पर सरकार एमएसपी रेट रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए 6,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। 2022-23 में एमसपी रेट में 6000 रुपए प्रति क्विंटल था।

जिले में नदियों में भी पानी की धारा कम हो गई, प्रशासन ने जल अभावग्रस्त जिला घोषित किया

बड़वानी में कम बारिश के कारण गिरा भूजल स्तर बगैर अनुमति ट्यूबवेल खनन पर लगा प्रतिबंध

बड़वानी। जागत गांव हमार

जिले में विगत वर्षों में कम बारिश होने के कारण भू-जल स्तर में आशानुरूप वृद्धि नहीं हुई है। आगामी गर्मी में और अधिक गिरावट होने की संभावना है इसके मद्देनजर कलेक्टर ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर पानी का उपयोग पीने व निस्तार के अलावा अन्य कार्यों में करने पर प्रतिबंधित लगा दिया है। जिले में गिरे हुए जलस्तर के कारण क्षेत्र के जलस्त्रोतों में भी पानी की कमी आने लगी है। नदियों की धारा छोटी होने के साथ ही मुहाने मैदान में नजर आने लगे हैं। दरअसल, कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने मप्र पेयजल परिरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 के अंतर्गत अन्य आदेश होने तक संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर जल स्त्रोतों कुएं, तालाब, नदी, हैंडपंप, ट्यूबवेल से पेयजल एवं निस्तार के लिए जल के उपयोग को छोड़कर अन्य उपयोग के लिए प्रतिबंध आदेशित किया है।

एसडीएम की लेना होगी अनुमति

बड़वानी में प्राकृतिक रूप से नर्मदा नदी को छोड़कर बहने वाली नदी-नालों तथा तालाबो में उपलब्ध पानी एवं भूमि सतह के नीचे पानी का घरेलू उपयोग एवं पशु धन के रख-रखाव के प्रयोजन के अतिरिक्त पानी की निकासी को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम में उपबंधित नियमानुसार अपने क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना तथा पूर्व से स्थापित नलकूप की 150 मीटर के रेडियस में कोई भी नलकूप खनन नहीं करवा सकेगा। बिना अनुमति अवैध उत्खनन के मामलों में उक्त अधिनियम में उपबंधित नियमानुसार अपने क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्रवाई करेंगे।

अब बंजर जमीन पर भी मिलेगा बंपर उत्पादन

वैज्ञानिकों ने तैयार की धान की अच्छी किस्म राज्यों के लिए केकेएल तीन किसी वरदान से कम नहीं

अब देश में होगी धान की बंपर परदावार

भोपाल। जागत गांव हमार

पुडुचेरी के कराईकल में एक कृषि संस्थान ने चावल की एक नई किस्म विकसित की है। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे लवणीय मिट्टी में भी असानी से उगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें मिट्टी की लवणता को सहन करने की भरपूर शक्ति मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ है कि किसान चावल की इस नई किस्म की खेती बंजर जमीन पर भी कर सकते हैं। केकेएल (आर) तीन नाम की इस नई किस्म को पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं की एक टीम ने विकसित किया है। शोध में पाया गया है कि खारा और सामान्य दोनों तरह की मिट्टी में केकेएल (आर) की खेती की जा सकती है। क्योंकि दोनों तरह की मिट्टी में इसका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। यह बंजर और सामान्य जमीन पर तेजी के साथ विकास करती है। यही वजह है कि शोधकर्ताओं ने बंजर जमीन पर खेती करने इस किस्म को ज्यादा उपयोगी माना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों के लिए केकेएल (आर) 3 किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी खेती करने से किसानों की इनकम में बढ़ोतरी होगी।

अब पूरे भारत में होगी इस किस्म की खेती

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह किस्म उत्तर भारत के जलवायु के लिए भी अनुकूल है। ऐसे में दक्षिण के साथ-साथ उत्तर भारत में भी किसानों को धान की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी जो किसान पहले बंजर जमीन पर किसी भी फसल की खेती नहीं करते थे, वे अब वहां पर धान की इस किस्म की खेती करेंगे। इससे देश में चावल की पैदावार बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा में मदद मिलेगी।

बंजर जमीन पर चावल की खेती

भारत, चीन के बाद सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल यहां की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल मानी जाती है। यह एक मुख्य भोजन है और देश की अधिकांश आबादी के लिए आहार का प्राथमिक स्रोत है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिचमाल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु सहित लगभग पूरे देश में चावल की खेती की जाती है, लेकिन हर साल लाखों एकड़ जमीन लवणीय होने के चलते खाली रह जाती है। किसान इन जमीनों पर धान की खेती नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब इस किस्म के आ जाने के बाद किसान असानी से केकेएल (आर) तीन किस्म की खेती लवणीय मिट्टी में भी कर पाएंगे।

आधुनिक उपकरण फसलों की कटाई के लिए किया गया डिजाइन

मप्र में हार्वेस्टर पर किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी

भोपाल। जागत गांव हमार

हार्वेस्टर यानी वह आधुनिक उपकरण जो आज किसानों के लिए कई तरह के अनाज के फसलों की कटाई के लिए डिजाइन किया गया है। हार्वेस्टर को अलग-अलग कामों, कटाई, मड़ाई, एकत्रीकरण और विनोइंग को एक साथ पूरा करने के मकसद से डिजाइन किया गया था। आज के समय में खेती के कामों की कल्पना बिना किसी यंत्र के करना मुश्किल होता है। देश के कई राज्यों की तरह ही मध्य प्रदेश में भी सरकार की तरफ से हार्वेस्टर खरीदने के लिए 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में अगर वहां के किसानों को अगर हार्वेस्टर खरीदना है तो उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिल सकती है।

किसानों को जहां 50 फीसदी की सब्सिडी मिलती है तो वहीं अगर उनके पास बाकी की राशि नहीं है तो वह सरकारी योजना से लोन भी ले सकते हैं। हार्वेस्टर स्कीन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को 50 फीसदी की सब्सिडी मिलती है। जबकि सामान्य वर्ग के किसान को 30 से 40 फीसदी तक की सब्सिडी मिलती है। हार्वेस्टर सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप मध्यप्रदेश सरकार कृषि उपकरण की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।

इस तरह करें अप्लाई

यहां पर आपको हर तरह के कृषि यंत्र नजर आएंगे और यहीं पर एक जगह हार्वेस्टर की फोटो होगी। इसके नीचे ही आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा। इसमें यहां पर सभी जानकारियों को ध्यान से भरना होगा। यहां पर सबसे पहले जिला ,ब्लॉक, गांव को चुनना होगा। अपना वर्ग चुनें, कृषि उपकरणों के प्रकार ,आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसी सभी जानकारियों को भरना होगा। इस तरह से आप हार्वेस्टर के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जरूरी शर्तें

किसान को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। किसान को पिछले सात सालों से किसी भी सरकारी योजना से कृषि उपकरण नहीं लिया होना चाहिए। आवेदक के बैंक खाता से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड, जमीन का कागजात, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत रहती है।

कैंपस के कंज्यूमर से सीधे जुड़ेंगे किसान, जेएनयू में मंथन

किसानों को नया बाजार उपलब्ध करवाने के लिए बनेंगे कैंपस कॉपरेटिव

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 1,113 विश्वविद्यालयों और 43,796 कॉलेजों में 4 करोड़ से अधिक युवा उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

यह वर्ष 2020-21 का आंकड़ा है। यानी शैक्षणिक कैंपस में एक बड़ा कंज्यूमर आधार है। जिसमें इनकी खानपान की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी तक बाजार और बिचौलियों का सहारा लिया जाता रहा है।

अब एक ऐसा मंत्र दिया जा रहा है कि इसे कॉपरेटिव से जोड़कर कैंपस और किसानों दोनों को फायदा दिलाया जाए।

इसी थीम के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉपरेटिव फोरम और नेशनल कॉपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में देश के जाने-जाने सहकारी नेताओं ने मंथन किया। ताकि एक ऐसा रोडमैप तैयार किया जा सके कि विश्व विद्यालयों में कैंपस कॉपरेटिव बनाकर सीधे किसानों को कैसे लाभ दिलाया जाए।

विश्व वानिकी दिवस पर विशेषः पर्यावरण की सबसे बड़ी हितरक्षक वानिकी

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड) म.प्र.

प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन एक ईश्वर प्रदत्त सृष्टि की रचना हैं। जिसमें जल, जंगल, जमीन, जलवायु, जानवर, पशु-पक्षी एवं मानव सभी समाहित हैं। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि की रचना में जरा सा भी खोट आता है तो संपूर्ण पारिस्थितिकी संतुलन डगमगा सकता है। इसलिए सृष्टि को बचाए रखने के लिए जंगल और वानिकी को बचाना ही होगा। पर्यावरण और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं।

पर्यावरण और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी जंगल और वानिकी है। भारत में सामाजिक वानिकी एवं संरक्षित वन इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। भारत में वानिकी एक महत्वपूर्ण ग्रामीण उद्योग और एक प्रमुख पर्यावरणीय संसाधन है। भारत विश्व के 10 सबसे अधिक वन संपदा वाले देशों में से एक है। भारत और नौ अन्य देश मैं दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 67 प्रतिशत हिस्सा आता है। वर्ष 1990 से 2000 के दौरान भारत का वन क्षेत्र 0.20 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है। इसके बाद वर्ष 2000 से लेकर 2010 के दौरान 0.7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भारत में वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। जबकि पूर्व के दशको में भारत में वन क्षेत्र का क्षरण गंभीर चिंता का विश्व विषय रहा है। वर्ष 2010 तक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान था कि भारत का वन क्षेत्र लगभग 68 मिलियन हेक्टर या देश के क्षेत्रफल का 22 प्रतिशत तक हो गया था। जबकि वर्ष 2013 के भारतीय वन सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत का वन क्षेत्र बढ़कर 69.8 प्रतिशत तक हो गया है। भारत के वन क्षेत्र में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारतीय राज्यों में देखी गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2018 तक भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 24.39 प्रतिशत तथा 2019 में यह और बढ़कर 24.56 प्रतिशत तक हो गया है। राज्यों के दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम , ओड़िसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप केरल,जम्मू कश्मीर, कर्नाटक राज्य प्रमुखता से आते हैं। भारत में हरियाणा राज्य वन आवरण के दृष्टिकोण से सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। हरियाणा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 3.5 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है। जनसंख्या के हिसाब से आबादी में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.88 प्रतिशत क्षेत्रफल जंगल और वानिकी के अंतर्गत आता है।

वर्ष 2019 के वन सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। वन आवरण प्रतिशत के दृष्टिकोण से मिजोरम 85.41 प्रतिशत वाला सर्वाधिक वन समृद्ध राज्य है। जबकि वन आवरण में कमी वाले राज्यों में प्रमुख रूप से मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। भारत सरकार की वन जनगणना एवं वर्ष 2021 वन आवरण के मानचित्र के अनुसार क्रमशः मध्य प्रदेश 77482, अरुणाचल प्रदेश 66688, छत्तीसगढ़ 55611, उड़ीसा 51619 एवं महाराष्ट्र 50778 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र वाले प्रमुख राज्य हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से

देखें तो भारत में वन एवं वानिकी क्षेत्र से निरंतर आय प्राप्त होती है। भारत के महत्वपूर्ण वन उत्पादों में कागज, प्लाईवुड, चंदन, लकड़ी, डंडे, लुगदी, माचिस की लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, साल के बीज, तेंदू के पत्ते, गोंद, रेजिन, चिरौंजी, महुआ, बेत, रतनजोत, बांस, घास, चारा, औषधियां, मसाले, जड़ी-बूटियां प्रमुख रूप से शामिल हैं।सौंदर्य प्रसाधन के रूप में टैनिन प्राप्त होता है। इसके साथ ही विश्व में भारत वन उत्पादों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक भी है।

पेड़-पौधे, जंगल, वन, वानिकी एवं सामाजिक वानिकी मानव जाति के जीने के लिए उतना ही जरूरी है जितना के खाने के लिए अन्य और पीने के लिए पानी है। क्योंकि पेड़-पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वहीं वृक्ष प्राणियों द्वारा छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमें जीने के लिए प्राण वायु प्रदान करते हैं। घने वृक्ष एवं जंगल अच्छी वर्षा करने के लिए उत्तरदाई भी हैं। ऐसे में मानव एवं प्राणियों की जीवन रक्षा के लिए वृक्ष एक अमूल्य धरोहर का कार्य करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण के साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं वह पर्यावरण के लिए कितने हित रक्षक हैं।

वृक्षों कई प्रजातियां जैसे कि यूकेलिप्टस, इलेस्टोनिया आदि वृक्ष जिन पर कि कभी पतझड़ नहीं होता है। पतझड़ ना करने वाले वृक्ष पर्यावरण के अनुकूल नहीं माने जाते हैं। बताया जाता है कि ऐसे वृक्ष जमीन से ज्यादा मात्रा में पानी खींचकर वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में उड़ा देते हैं जिससे जमीन के अंदर भूगर्भ जलस्तर में कमी आती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें ऐसे पेड़-पौधों का चयन करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल एवं इमारती लकड़ी के साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक हैं।

आज खेती में भी कृषि वानिकी की जा रही है। कृषि वानिकी के कई रूप आज चलन में हैं। कृषि वानिकी के माध्यम से लकड़ी, चारा, फसल उत्पादन, औषधि उत्पादन आदि प्राप्त किया जा सकता है। कृषि वानिकी से पेड़ों के साथ फसलों और पशुधन की विविधता में वृद्धि होती है जो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को बढ़ावा और संरक्षित करते हैं। देश में स्थानीय कृषि वानिकी ज्ञान वर्षों से जमा हुआ है, जो मुख्य रूप से अपनी जातीय वानिकी प्रथाओं और विविध वृक्ष प्रजातियों को उगाने के लिए स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में, कृषि वानिकी प्रणालियों पर वैज्ञानिक ज्ञान जुटाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए वानिकी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। आज समय की मांग है कि वनों को अधिका-अधिक सरक्षित करने के साथ ही सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने की जरूरत है। क्योंकि वन क्षेत्र को बढ़ाने की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों के माध्यम से सामाजिक वानिकी के दायरे को अधिक से अधिक बढ़ाया जाना संभव है।

खुरपका-मुंहपका रोग को समझना और इसके खिलाफ भारत की लड़ाई

» डा. रविंदर
» डॉ. प्रगति पटेल
» डॉ. आदित्य मिश्रा
» डॉ. आनंद कुमार जैन
» डॉ. पूर्णिमा सिंह
» डॉ. संजू मंडल
» डॉ. अनिल गट्टानी

पशु चिकित्सा विज्ञान विवि. जबलपुर

एफएमडीवी जानवरों या मनुष्यों की सबसे अधिक संक्रामक बीमारियों में से एक है, और एफएमडीवी तेजी से संक्रमित जानवरों के भीतर, संपर्क में आने वाले अतिसंवेदनशील जानवरों के बीच और एरोसोल द्वारा फैलता है। रोग के लक्षण संपर्क में आने के 2 से 3 दिनों के भीतर प्रकट हो सकते हैं और 7 से 10 दिनों तक रह सकते हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर दुनिया भर के 69 देशों और 21 क्षेत्रों को टीकाकरण के साथ या बिना, एफएमडी मुक्त के रूप में मान्यता दी है। साथ ही, 100 से अधिक देश अभी भी इस बीमारी से स्थानिक या छिटपुट रूप से प्रभावित माने जाते हैं।

प्रेरक एजेंट, एफएमडी वायरस, पिकोर्नविरिडे परिवार के एफ्थोवायरस जीनस से संबंधित है। वर्तमान में, एफएमडीवी सीरोटाइप ओ, ए, एशिया1, दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र-1, एसएटी-2 और एसएटी-3 विश्व स्तर पर प्रचलित छह एंटीजेनिक रूप से विशिष्ट सीरोटाइप हैं। 2004 के बाद से दुनिया के किसी भी हिस्से में एफएमडीवी सीरोटाइप सी की सूचना नहीं मिली है।

अतिसंवेदनशील पशुधन जनसंख्याः पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25.6% और राष्ट्रीय जीडीपी में 4.11% का योगदान देता है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 2019 की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत में मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मिथुन और याक सहित फुट एंड माउथ डिजीज-अतिसंवेदनशील पशुधन की एक बड़ी आबादी है। एफएमडी-अतिसंवेदनशील पशुधन की आबादी दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में काफी समान रूप से वितरित की जाती है, जिनमें से प्रत्येक कुल आबादी का 19-22% है। हालाँकि, मध्य (10%) और उत्तर-पूर्वी (5%) क्षेत्रों में अतिसंवेदनशील पशुधन का अनुपात अपेक्षाकृत कम है।

प्रयोगशाला निदानःभारत में एफएमडी निगरानी नेटवर्क में एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला, आईसीएआर-डीएफएमडी और तीस राज्य एफएमडी क्षेत्रीय और सहयोगी केंद्र शामिल हैं, जो रोग नियंत्रण के लिए आवश्यक वायरस का प्रारंभिक पता लगाने और सीरोटाइप पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। एफएमडी निदान के लिए पूरक निर्धारण परीक्षण, वायरस न्यूट्रलाइजेशन परीक्षण, एंजाइम-लिंक्ड इम्युनोसॉरबेंट परख, और पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन सहित विभिन्न नैदानिक परखों का उपयोग किया जाता है। टाइपिंग के लिए बीएचके-21 कोशिकाओं में वायरस अलगाव के साथ नमूनों की जांच के लिए सैंडविच एलिसा और मल्टीप्लेक्स पीसीआर को नियमित रूप से नियोजित किया जाता है। 2011 और 2020 के बीच संदिग्ध एफएमडी प्रकोप से 9770 नैदानिक नमूने संसाधित किए गए, जिनमें सीरोटाइप ओ सबसे अधिक प्रचलित (46.8%) था, इसके बाद एशिया1 (2.5%) और ए (1.5%) का स्थान था। भारत में चार एफएमडीवी सीरोटाइप (ओ, ए, सी और एशिया1) की पहचान की गई है, जिनमें सीरोटाइप सी 1995 के बाद से रिपोटज़ नहीं किया गया है। सीरोटाइप ओ ऐतिहासिक रूप से प्रमुख रहा है, इसके बाद एशिया1 और ए हैं। 2011 और 2020 के बीच, 2226 एफएमडी का प्रकोप दर्ज किया गया था, 2013 और 2018 में चरम प्रकोप के साथ और 2020 में गिरावट का कारण संभवतः कोविड से संबंधित गतिविधि प्रतिबंध था। 2011 के बाद से टीकाकरण कार्यक्रमों का विस्तार हुआ, अधिक जिलों को कवर किया गया और संभवतः प्रकोप को कम करने में योगदान दिया गया। अधिकांश प्रकोपों (70.9-100%) के लिए सीरोटाइप ओ जिम्मेदार है, जबकि सीरोटाइप ए में लगातार गिरावट आई और सीरोटाइप एशिया1 में विविधताएं दिखाई दीं।

एफएमडी प्रकोप का अस्थायी वितरणःएफएमडी सहित संक्रामक रोग का प्रसार अक्सर तापमान, धूप, आर्द्रता और वायु प्रदूषण जैसे कारकों से प्रभावित मौसमी भिन्नता प्रदर्शित करता है, जो मेजबान प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। मौसम की स्थिति एयरोसोलिज्ड एफएमडीवी के अस्तित्व और संचरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के सर्दियों के महीनों के दौरान चरम संचरण देखा जाता है। वायरस फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में कम वर्षा, स्थिर हवा का प्रवाह और मध्यम हवा की गति शामिल हैं। भारत में एफएमडी का प्रकोप पूरे वर्ष होता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च के दौरान चरम पर होता है।

वैक्सीन मिलान मूल्यांकनः वर्तमान में, भारत में उपयोग किए जाने वाले ट्राइवैलेंट वैक्सीन फॉर्मूलेशन में O/IND R2/1975, A/IND40/2000, और Asia1/IND63/ 1972 स्ट्रेन शामिल हैं। 2011 और 2020 के बीच किए गए वैक्सीन मिलान अध्ययनों से पता चला कि O/IND R2/1975, औरAsia1/IND63/ 1972 उपभेदों ने क्रमशः 88% और 80% फील्ड आइसोलेट्स के साथ अच्छी एंटीजेनिक संगतता प्रदर्शित की, जो वर्तमान वैक्सीन फॉर्मूलेशन के लिए उनकी उपयुक्तता का संकेत देती है। हालाँकि, सीरोटाइप ए फील्ड वायरस के एक महत्वपूर्ण अनुपात (75.6%) ने A/IND 40/2000 वैक्सीन स्ट्रेन से एंटीजेनिक बहाव प्रर्दशित किया, जिससे इस विचलन को संबोधित करने के लिए एक नए स्ट्रेनA/IND27/2011 के चयन की आवश्यकता हुई। जबकि सीरोटाइप ओ वैक्सीन स्ट्रेन आम तौर पर व्यापक-स्पेक्ट्रम सुरक्षा प्रदान करते हैं, सीरोटाइप ए का प्रकोप एंटीजेनिक रूप से अलग-अलग वेरिएंट के आवधिक उद्भव के कारण चुनौतियां पेश करता है, जिसके लिए हर 5 से 10 वर्षों में नए वैक्सीन स्ट्रेन के विकास की आवश्यकता होती है।

भारत में, खुरपका-मुंहपका रोग 2011 से 2020 तक प्रचलित था, जिसमें सीरोटाइप ओ मुख्य रूप से प्रकोप का कारण था, जबकि सीरोटाइप ए और एशिया1 छिटपुट थे। एफएमडीवी सीरोटाइप ओ की उभरती वंशावली के कारण 2013 और 2018 में राष्ट्रव्यापी महामारी हुई। भारत 2003-04 में शुरू किए गए टीकाकरण-आधारित नियंत्रण कार्यक्रम पर निर्भर है, जो धीरे-धीरे 2019 तक पूरे देश को कवर करने के लिए विस्तारित हुआ है। रोग की घटनाओं और नैदानिक संकेतों में सुधार के बावजूद- टीकाकरण, एक सख्त द्विवार्षिक टीकाकरण व्यवस्था को बनाए रखने में टीके की उपलब्धता और हितधारक की भागीदारी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी तैनाती से इन मुद्दों का समाधान होने और रोग नियंत्रण प्रयासों में वृद्धि होने की उम्मीद है।

कपड़ों पर लगे दाग धब्बे कैसे छुड़ाएं

डा. पल्लवी सिंह
पीएचडी, 'पारिवारिक संसाधन प्रबन्ध एवं उपभोक्ता विज्ञान विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

हमारे दैनिक या रोजमर्रा के जीवन में कपड़ों या वस्त्रों पर दाग धब्बे लगना साधारण सी बात है जो की कभी-कभी लापरवाहीबस या कभी-कभी अनजाने में लग जाते हैं। वस्त्रों पर दाग एक प्रकार का चिन्ह या धब्बा है, जो वस्त्रों पर एक अलग रंग के रूप में दिखाई देता है जो वस्त्रों के वास्तविक स्वरूप को खराब कर देता है। कुछ दाग धब्बो को तो आसानी से छुड़ाया जा सकता है, किन्तु कुछ ऐसे भी दाग धब्बे होते हैं जिन्हे छुड़ाने के लिए विशेष प्रकार की विधि की आवशकता होती है, विधि कौन सी अपनानी होगी यह दाग धब्बों की प्रकति पर निर्भर करता है। ऐसे में इंक, धूल, आयल, फल, चाय, ग्रीस आदि हो सकते है।

दाग धब्बो को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं-
जंतु जनित दाग, वानस्पतिक दाग, ग्रीस जनित रोग, डाई के दाग, एवं खनिज जनित दाग।

जंतु जनित दागः खून से, अंडे से, तथा मीट के रस आदि से लगने वाले दाग जंतु जनित दाग कहलाते हैं। ऐसे दागों को ताप से दूर रखना चाहिए। ताप के संपर्क में आने पर प्रोटीन दाग के रूप में नजर आने लगता है।

वानस्पतिक दागः चाय कोको, काफी, तथा फलों आदि के जूस के धब्बे शामिल है। ये अमलीय प्रकति के होते हैं अतः इन्हे छुड़ाने के लिए चरिया माध्यम की आश्वकता होती है।

ग्रीस जनित दागः इनमे ज्यादातर घी, आयल , बटर , पेण्ट वेर्निस आदि के गाड़ धब्बे शामिल है। **खनिज जनित दागः** इसमें जंग, इंक, दवाओं आदि के दाग आते हैं।

विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे छुड़ाने के तरीके

जंग के दागः दाग को प्लेट की सतह पर फैलाएं। धूप में रखें। आक्सैलिक एसिड की पोटली बनाकर पानी में डुबो कर धब्बे पर रगड़े फिर कुछ समय धुप में रखे दाग छूट जाने पर अच्छी तरह पानी से वस्त्र को धोखा डालें, जिससे एसिड का प्रभाव समाप्त हो जाए।

पकी हुई सब्जी, हल्दी के दागः इस प्रकार के धब्बो को साबुन और पानी के घोल से साफ करें। सिल्क एवं गरम वस्त्रो पर लगे दाग को और के घोल से धीरे धीरे छुड़ाए। इंक के धब्बो को सूती वस्त्र से स्पिरिट में डुबोकर साफ करं। इसके अतिरिक्त इंक लगे स्थान को प्लेट पर रखे , उस पर नमक की परत लगाकर नीबू का रस निचोड़कर साफ करें, फिर पानी से साफ कर दें। इसका साधारण तरीका यह है की ब्लीचिंग पाउडर या कच्चा दूध या इंक रेमोवेर से साफ करना अच्छा होता है। इंक के धब्बो को सूती वस्त्र से स्पिरिट में डुबोकर साफ करें। इसके अतिरिक्त इंक लगे स्थान को प्लेट पर रखे, उस पर नमक की परत लगाकर नीबू का रस निचोड़कर साफ करें , फिर पानी से साफ कर दे। इसका साधारण तरीका यह है की ब्लीचिंग पाउडर या कच्चा दूध या इंक रेमोवेर से साफ करना अच्छा होता है।

तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मूली, धनिया और लौकी की खेती कर किसान कम समय में हासिल कर सकते हैं अच्छी उपज

गर्मी के मौसम में सब्जी की खेती किसानों को कर सकती है मालामाल

बेहतर सिंचाई की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, फसल तैयार होने में 80 से 90 दिनों का समय लगता है...

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में अब गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है। रबी सीजन के फसलों की कटाई चल रही है। कई किसानों से रबी फसलों की कटाई कर ली है. साथ ही आलू की खुदाई के बाद अब खेत खाली हो गए हैं। ऐसे में किसान अब जायद फसलों की तैयारी कर रहे हैं। गर्मियों में आम तौर पर वहीं किसान खेती कर पाते हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधा होती है। आमतौर पर गर्मियों में सरसों, गेहूं और दलहनी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाता है। इसके बाद किसान गरमा सब्जियों की खेती करते हैं। इनमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मूली, धनिया और लौकी जैसी सब्जियां शामिल हैं। यह ऐसी खेती हैं जो बेहद कम समय में तैयार हो जाती है और इसे बेचकर किसान पैसे कमा सकते हैं तो इस खबर में हम आपको कुछ ऐसे ही सब्जियों के बारे में बताएंगे जिनकी खेती करके किसान कम समय में अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही गर्मियों में इनकी मांग भी अधिक रहती है इसलिए बाजार में जल्दी आने से किसानों को इसके अच्छे दाम भी मी मिल जाते हैं। गर्मियों के लिए इनकी खेती इसलिए भी फायदेमंद होती है क्योंकि कम सिंचाई में भी यह बेहतर उपज देती है।

कम सिंचाई में होता है खरबूजा

खरबूजा की खेती साल में एक ही बार गर्मी के सीजन में होती है। सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही इसे उगाया जाता है। यह खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है और इसे खाने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। खरबूजा की खेती रेलीती जमीन पर होती है। इसमें इसकी पैदावार अधिक होती है। खास बात यह है कि इसकी खेती में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। इसलिए इसकी खेती में किसान कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

जल्दी तैयार होती है मूली

मूली की खेती किसी भी फसल सीजन में की जा सकती है, पर गर्मियों में इसकी अधिक मांग होती है, क्योंकि इसे सलाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसके पत्तियों को साग के तौर पर खाया जाता है। इसके खेती करने का फायदा यह है कि यह बेहद कम समय में तैयार हो जाती है। बाजार में अब इसकी ऐसी उन्नत किस्में भी आ गई है जो 40-50 दिन में खाने लायक तैयार हो जाती है।

कम लागत में ज्यादा मुनाफा

गर्मियों के मौसम में खीरा की बाजार में बहुत मांग होती है और इसके अच्छे दाम भी मिलते हैं। खीरा एक ऐसी फसल है जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बाजार में इसकी ऐसी भी किस्में हैं जो लगभग 50-60 दिनों में तैयार हो जाती है। कम समय में यह अच्छी पैदावार देती है। इसके अलावा इसकी खेती में लागत कम लगती है पर मुनाफा अधिक होता है।

धनिया की खेती के फायदे

धनिया पत्ते की मांग तो वैसे सालों भर रहती है पर गर्मियों में इसकी मांग अधिक हो जाती है। धनिया की खेती किसानों के लिए फायदेमंद इसलिए होती है, क्योंकि यह मात्र 35-40 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके अलावा इसकी खेती में कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होता है। गर्मियों के लिए इसकी खेती इसलिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसकी खेती में कम सिंचाई करने के भी काम हो जाता है। कम लागत और कम समय में इसकी खेती होने के कारण किसानों को इसमें अच्छा मुनाफा होता है।

तरबूज की मांग

तरबूज का सेवन गर्मियों में सबसे अधिक किया जाता है। यह इसका सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है इसलिए गर्मियों में इसली मांग भी खूब होती है। इसकी खेती में किसानों को काफी मुनाफा होता है, पर इसकी खेती में किसानों को पूंजी भी लगानी पड़ती है। साथ ही बेहतर सिंचाई की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इसकी फसल तैयार होने में 80 से 90 दिनों का समय लगता है।

मक्का और मूंगफली के रकबे में वृद्धि दर्ज, देशभर में 27 लाख हेक्टेयर हुआ धान का रकबा, उड़द की बुवाई में भी मामुली वृद्धि

ग्रीष्मकालीन फसलों की बोवनी में 7 फीसदी इजाफा

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों ने रबी फसलों की कटाई करने के साथ-साथ ग्रीष्मकालीन फसलों की बोवनी भी शुरू कर दी है, जो मई महीने तक जारी रहेगी। खास बात यह है कि पूरे देश में अभी 39.44 लाख हेक्टेयर में किसानों ने ग्रीष्मकालीन फसलों की बोवनी की है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक है। इस बार धान, मक्का और मूंगफली के रकबे में वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि सूरजमुखी, बाजरा और रागी जैसी कुछ अन्य फसलों का रकबा पिछले साल से कम है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, धान की बोवनी 8 प्रतिशत बढ़कर 27.08 लाख हेक्टेयर हो गई है, जबकि मोटे अनाज का क्षेत्रफल 9.1 प्रतिशत बढ़कर 4.19 हेक्टेयर हो गया। मोटे अनाजों में, मक्के का क्षेत्रफल 24.2 प्रतिशत बढ़कर 2.99 लाख हेक्येयर हो गया है, जबकि ज्वार 0.2 लाख हेक्टेयर पर लगभग दोगुना हो गया है। इसी तरह बाजरा का क्षेत्रफल 23 प्रतिशत घटकर 0.97 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। वहीं, ग्रीष्मकालीन दालों का क्षेत्रफल 0.5 प्रतिशत बढ़कर 3.23 लाख हेक्टेयर को छू गया है, जिसका मुख्य कारण अन्य छोटी स्थानीय दालों के कवरेज में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि है।

56 फीसदी कम बारिश

एक मार्च से प्री-मॉनसून सीजन में संचयी वर्षा 15 मार्च तक अखिल भारतीय आधार पर सामान्य से 8 प्रतिशत कम है। जबकि उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में 36 प्रतिशत की अधिकता है। मध्य भारत में 22 प्रतिशत कम बारिश हुई है। लंबी अवधि के औसत की तुलना में अब तक वर्षा हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 1-15 मार्च के दौरान दक्षिण में सामान्य से 96 फीसदी कम बारिश हुई है और पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में औसत से 56 फीसदी कम बारिश हुई है।

तिलहन क्षेत्र में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मूंग की फसल की बोवनी 0.6 प्रतिशत कम होकर 2 लाख हेक्टेयर हो गई, जबकि उड़द की बुआई 1 प्रतिशत बढ़कर 1.11 लाख हेक्टेयर बताई गई है। ग्रीष्मकालीन दालों के प्रमुख उत्पादक मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात हैं। इसी तरह तिलहन क्षेत्र में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका रकबा 4.94 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। इसमें मूंगफली 2.7 लाख हेक्टेयर और तिल 1.85 लाख हेक्टेयर शामिल है। जबकि, सूरजमुखी का रकबा 15 प्रतिशत कम होकर 19,000 हेक्टेयर रह गया है।

गेहूं, चना और सरसों की समर्थन मूल्य खरीदी के लिए बनाई रूपरेखा

33 केंद्रों पर होगी गेंहू की खरीदी और 11 पर किसानों से खरीदेंगे सरसों-चने की उपज

श्योपुर।प्रधान संपादक

रबी फसलों की कटाई के साथ ही अब जिले में तीन मुख्य फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि गेहूं की फसल तो अभी अप्रेल में आएगी, लेकिन सरसों की फसल मंडी में आ रही है। यही वजह है कि सरसों व चना की समर्थन मूल्य की खरीदी 26 मार्च से निर्धारित की गई है, जबकि गेहूं की खरीदी 29 मार्च से होगी। इसी के तहत जिले में सरसों व चना खरीदी के लिए 11 खरीद केंद्र निर्धारित किए गए हैं, वहीं गेहूं की खरीदी के लिए 33 केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में अब उम्मीद है कि होली के त्योहार के बाद जिले में तीनों फसलों की खरीद शुरू हो जाएगी। हालांकि गेहूं का समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि खुले बाजार में गेहूं के भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं, लिहाजा गेहूं केंद्रों पर आएगा या नहीं इसको लेकर असमंजस है। लेकिन सरसों का समर्थन मूल्य 5650 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि खुले बाजार में सरसों औसतन 5000 से 5100 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, लिहाजा श्योपुर जिले के किसान खरीदी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं

सरसों व चना के लिए ये होंगे केंद्र- कृषि विभाग के माध्यम से सरसों व चना की समर्थन मूल्य पर खरीद होगी, जिसके लिए मार्कफेड को एजेंसी बनाया गया है। इसके लिए 11 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें बड़ौदा सहकारी संस्था द्वारा राजकुमारी वेयरहाउस पर और उतनवाड़ सहकारी संस्था द्वारा मंडी बड़ौदा में खरीदी की जाएगी। वहीं सीडब्ल्यूसी श्योपुर पर सहकारी संस्था फिलोजपुरा, तुलसैफ और कनापुर के केंद्र रहेंगे, एसडब्यूसी श्योपुर पर मार्केटिंग श्योपुर और सहकारी संस्था सोंईकला के खरीद केंद्र रखे गए हैं। मानपुर सहकारी संस्था मानपुर मंडी प्रांगण में, कराहल मार्केटिंग संस्था कराहल मंडी में, वीरपुर मार्केटिंग वीरपुर मंडी प्रांगण में और विजयपुर मार्केटिंग सोसायटी विजयपुर मंडी में खरीद करेगी।

गेहूं खरीदी के लिए बनाए गए ये खरीद केंद्र

जिले में समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीदी के लिए प्रशासन के द्वारा 33 केन्द्र निर्धारित किए गए है,जहां समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीदी की जाएगी। बताया गया है कि गेंहू खरीदी के लिए जिन्हें खरीद केन्द्र बनाया गया है, उनमें आदिम जाति सहकारी संस्था आवदा, विपणन सेवा सहकारी संस्था कराहल, वृहताकार सहकारी संस्था बड़ौदा, सेवा सहकारी संस्था बोरदादेव, सेवा सहकारी संस्था नयागांव तेखंड, राडेप, लुहाड, वृहताकार सहकारी संस्था फिलोजपुरा, तलावड़ा,सेवा सहकारी संस्था नयागांव ढोढपुर, सेवा सहकारी संस्था उतनवाड, विपणन सेवा सहकारी संस्था वीरपुर, सेवा सहकारी संस्था ओछापुरा, रघुनाथपुर, वृहताकार सहकारी संस्था विजयपुर, विपणप सहकारी समिति विजयपुर, वृहताकार सहकारी संस्था श्योपुर, सेवा सहकारी संस्था जलालपुरा, नागदा, सोंईकलां, नागरगांवडा, ढोढर, आसीदा, विजरपुर, ननावद,गोहेड़ा, वृहताकार सहकारी संस्था दांतरदा, मानपुर, सेवा सहकारी संस्था जावदेश्वर, तलावदा, सोंठवा, गुरूनावदा, क्यारपुरा शामिल है।

गेहूं में सायलो के बजाय वेयरहाउस पर खरीद

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए भी प्रशासन ने 33 खरीद केंद्र निर्धारित किए हैं। हालांकि गेहूं खरीदी के लिए 29 मार्च की तारीख तय की है, लेकिन श्योपुर जिले में अप्रेल के पहले सप्ताह में ही गेहूं की आवक होने लगेगी, लिहाजा उसके बाद ही गेहूं की खरीदी शुरू होगी। लेकिन इस बार जिले में सायलो केंद्रों पर गेहूं खरीदी नहीं होगी, बल्कि निजी और सरकारी वेयरहाउस में केंद्र बनेंगे, साथ ही सहकारी संस्थाएं अपने गांवस्तर पर ही खरीद करेंगी। इस बार सायलो पर खरीदी न होने के कारण विरोध दिखाई पड़ रहा है।

गेहूं खरीदी के लिए हमने 33 खरीद केंद्र निर्धारित किए हैं। इसमें इस बार सायलो केंद्रों पर खरीदी केंद्र नहीं बनेंगे। 29 मार्च से गेहूं की खरीदी होनी है।
सुनील दत्त शर्मा, प्रभारी, आपूर्ति अधिकारी श्योपुर

खेती में प्रयोग होने वाले रासायनिक कीटनाशक अत्यंत घातक

लहार। प्राकृतिक खेती परियोजना अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र पर 10वें बैच का दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषक एवं कृषक महिलाओं को प्राकृतिक खेती की बारीकियों के साथ ही प्राकृतिक कृषि के उत्पादों को प्रशिक्षण के दौरान बनाकर भी सिखाया गया।

इस अवसर पर केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि प्राकृतिक कृषि भविष्य की खेती है। किसानों द्वारा लगातार रासायनिक खेती करने के कारण जमीन की उर्वरा शक्ति छीड़ होने के साथ ही भूमि में जीवांश एवं लाभकारी मित्र कीट पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। इसके चलते खेत की मिट्टी रेत में तब्दील हो रही है, जिससे भूमि की जलधारण क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। किसान प्राकृतिक कृषि की ओर उन्मुक होते हैं। भूमि में जैविक उर्वरक एवं गोबर की खाद, केंचुआ की खाद, हरी खाद आदि का भी प्रयोग करें तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ ही जमीन में जीवाश्म का भी प्रतिशत बढ़ेगा। खेती पर आने वाली लागत घटेगी तथा मृदा और मानव स्वास्थ्य भी बच सकेगा। उन्होंने बताया कि हानिकारक रसायन व कीटनाशक अत्यंत घातक हैं। इसे मानव एवं पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। कई प्राण घातक बीमारियां पैदा हो रही हैं। इनसे बचाव के विकल्प विकल्प के तौर पर प्राकृतिक कृषि ही मानव एवं पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए के लिए अत्यंत जरूरत है। प्रशिक्षण में केंद्र के मृदा वैज्ञानिक एवं परियोजना प्रभारी डॉ.भानु प्रताप सिंह रघुवंशी ने बताया कि प्राकृतिक कृषि में जीवामृत, वीजामृत, घनजीवामृत के साथ ही नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र आदि बनाकर प्राकृतिक कृषि को असानी से कर सकते हैं। डॉ. रघुवंशी ने बताया कि अग्निआस्त्र बनाने के लिए 5 किलो नीम की पत्ती, एक किलो तंबाकू, आधा किलो हरी मिर्च, एक किलो लहसुन एवं 15 से 20 लीटर गोमूत्र की जरूरत होती है। इन सभी को कूट-पीसकर गौमूत्र में उबाल कर तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण में केंद्र के उद्यानिकी वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. करणवीर सिंह ने बताया कि सब्जियों की खेती में प्राकृतिक कृषि का महत्वपूर्ण रोल होता है। सब्जी फसलों में प्राकृतिक कृषि के उत्पादों के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। अत: किसान प्राकृतिक कृषि उत्पाद अपना कर सब्जी की खेती की ओर आगे बढ़े तो सब्जियों में आने वाले जहरीले रसायनों को रोखकर मानव स्वास्थ्य को बचाया जा सकता है।

किसान लें बीज और बीजोपचार की सलाह, वैज्ञानिक तरीके अपनाकर कमा सकते हैं लाभ

किसानों को आर्थिक समृद्धि दिलाएगी मूंगफली की उन्नत खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

मूंगफली भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। यह ज्यादातर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्यों में उगाया जाता है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे अन्य राज्यों में भी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। राजस्थान में इसकी खेती लगभग 3.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिससे लगभग 6.81 लाख टन उत्पादन होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों ने मूंगफली की उन्नत तकनीकें जैसे उन्नत किस्में, रोग नियंत्रण, निराई और खरपतवार नियंत्रण आदि विकसित की गई हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कब की जाती है मूंगफली की बोवनी। साथ ही बोवनी करने करने के लिए कहां से लें बीज और कैसे करें बीजोपचार, हम किसानों को बता रहे हैं।

मूंगफली की बोवनी का सही समय: बोवनी का सही समय जून का पहला सप्ताह है। मध्यम आकार की झुमका किस्मों की 100 किग्रा और फैलने वाली अर्ध फैलने वाली किस्मों की 80 किग्रा प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त है। झुमका किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेमी सही मानी जाती है। साथ ही फैलने वाली और अर्ध फैलने वाली किस्मों के लिए 45 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखा जाना चाहिए। ऊंची क्यारियों में बुआई करने पर बीज की उपज और गुणवत्ता बढ़ जाती है।

बोवनी से पहले करें बीजोपचार

कॉलर रॉट रोग की रोकथाम के लिए कार्बोक्सिन 37.5 प्रतिशत और थीरम 37.5 प्रतिशत (विटावेक्स पावर) 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर पर बीजोपचार करें। सफेद लट की रोकथाम के लिए बीजों को 6.5 मिली में मिला देना चाहिए। इमिडाक्लोप्रिड 600 एफएस प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर बोएं।

मूंगफली में खाद की जरूरत

उर्वरकों का उपयोग भूमि के प्रकार, उसकी उर्वरता, मूंगफली की विविधता, सिंचाई सुविधाओं आदि के अनुसार किया जाता है। मूंगफली, दलहन परिवार की तिलहनी फसल होने के कारण, आमतौर पर नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हल्की मिट्टी में 15-20 किग्रा नाइट्रोजन और शुरुआती वृद्धि के लिए 50-60 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होती है। फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना लाभकारी रहता है। उर्वरक की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही भूमि में मिला देनी चाहिए। कम्पोस्ट या गोबर की खाद उपलब्ध हो तो इसकी 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर मात्रा बुआई से 20-25 दिन पहले खेत में बिखेर कर अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। अधिक उत्पादन के लिए 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई से पहले भूमि में मिला देना चाहिए।

कर्जमाफी की उम्मीद में तय समय सीमा में नहीं चुकाया कर्ज, बंद हो जाएगी सोसायटियों से खाद बीज की सुविधा

किसान भी कर्ज चुकाने में गंभीरता नहीं दिखा रहे

जिले 31 हजार 924 किसानों पर 79 करोड़ से ज्यादा का कर्ज, हो सकते हैं डिफाल्टर

जागत गांव हमार, श्योपुर।

चुनावी दौर में कर्जमाफी हर बार बड़ा मुद्दा होता है। विधानसभा चुनाव प्रचार के शोर में भी कर्जमाफी खूब गूंजा था, इस बार भी जिले के हजारों किसानों ने सोसायटियों का कर्ज अब तक जमा नहीं किया है। चुनावी समर में किसान माफी के इंतजार में कर्ज जमा नहीं करता है। दरअसल, अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जिस कारण किसानों को कर्जमाफी की उम्मीद लग रही है। इसलिए किसान सोसायटियों का कर्ज चुकाने में गंभीरता नहीं दिखा रहे है। यही वजह है कि जिले की 47 सोसायटियों से जुड़े 31 हजार 924 किसानों पर 79 करोड़ 2 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। तय समय सीमा में ये कर्ज नहीं चुकाने पर जिले के इतने सारे किसान डिफाल्टर घोषित हो जाएंगे।

जिसके बाद डिफाल्टर होने वाले किसानों को आगामी फसल के लिए सोसायटियों से खाद बीज की सुविधा मिलना बंद होने के साथ-साथ नियमित लेन-देन भी बंद हो जाएगा। बता दें कि जिले में 47 सोसायटियां संचालित हैं। जिनसे जिले के किसान खरीफ और रबी फसल के लिए हर साल न सिर्फ खाद बीज उधार देते है, बल्कि नियमित लेनदेन भी करते है। बीते खरीफ और रबी सीजन की फसलों के लिए किसानों के द्वारा सोसायटियों से खाद बीज के लिए कर्ज लिया गया है। जिसके चलते जिले के 31 हजार 924 किसानों पर 79 करोड़ 2 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है।

फैक्ट फाइल

- 47 सोसायटियां जिले में
- 15798 कर्जदार किसान
- 55 करोड रुपए कर्ज की राशि
- 30 अप्रैल कर्ज जमा करने की अंतिम तिथि

कर्ज चुकाने के लिए 28 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित थी,मगर अब शासन स्तर से ये तिथि 30 अप्रैल हो गई है। खरीफ सीजन का कर्जा 30 अप्रैत तक न चुकाने पर 15 हजार से ज्यादा किसान डिफाल्टर हो जाएंगे। डिफाल्टर की कार्रवाई से बचने के लिए किसान कर्ज की राशि समय सीमा में जमा करवाए।
दिनेश कुमार गुप्ता, नोडल अधिकारी,जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्योपुर

55 करोड़ तो अब 30 अप्रैत तक चुकाने होंगे

जिले के 31 हजार 924 किसानों पर सोसायटियों का 79 करोड़ 2 लाख रुपए का कर्जा है। बताया गया है कि खरीफ सीजन में जिले के 15 हजार 798 किसानों के द्वारा खादी बीज सहित अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए 55 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। जबकि रबी सीजन में 15 हजार से ज्यादा किसानों के द्वारा 24 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। विभागीय अधिकारियों की माने तो पहले तो खरीफ सीजन का कर्जा जमा किए जाने के लिए 28 मार्च की अंतिम तिथि शासन के द्वारा निर्धारित की गई थी। लेकिन अब ये अंतिम तारीख 28 मार्च से बढाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। इसलिए अब 15 हजार 798 किसानों को खरीफ सीजन का कर्ज जमा करने का मौका 30 अप्रैल तक का अवसर मिल गया है। यदि 30 अप्रैल तक भी ये किसान 55 करोड़ का कर्ज नहीं जमा कर पाएंगे तो जिले के 15 हजार 798 किसान डिफाल्टर हो जाएंगे। जबकि रबी सीजन का कर्जा जून तक जमा कराना होगा।

ओवरड्यू किसानों को नहीं मिलता लाभ

किसान डिफाल्टर होने के बाद सोसायटियों से लाभ मिलना बंद हो जाता है। सबसे अधिक किसानों को रबी व खरीफ सीजन में खाद के लिए परेशान होना पड़ता है। कर्ज जमा नहीं होने की स्थिति में ब्याज की पैनल्टी बढ़ने के साथ किसान डिफाल्टर भी हो जाता है। ऐसे में नियमित लेन-देन सोसायटियों से नहीं होता है तो किसानों को खाद की सुविधा भी नहीं मिलती। ऐसे में किसानों को नगद केंद्र पर खाद लेना पड़ता है और कभी कभी अधिक दाम भी चुकाना पड़ता है, लंबी कतारों में लगकर खाद के लिए परेशान होना पड़ता है।

समाधान खोजने की कोशिश में जुटे देश के कृषि वैज्ञानिक

कपास की फसल में गुलाबी सुंडी ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत

भोपाल। जागत गांव हमार

कपास की खेती के लिए गुलाबी सुंडी सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभर रहा है। इससे निपटने के लिए किसानों को कीटनाशकों पर काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जिससे खेती की लागत बढ़ रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की ओर से विश्वविद्यालय में इसके मैनेजमेंट के लिए एक बैठक आयोजित की गई। कुलपति बीआर कम्बोज ने कहा कि देश के उत्तरी क्षेत्र में लगातार गुलाबी सुंडी के बढ़ते प्रकोप के समाधान के लिए हमें सामूहिक रूप से एकजुट होकर काम करना होगा। ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। बैठक में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक, अधिकारी, निजी बीज कंपनियों के प्रतिनिधि और कपास उगाने वाले 10 जिलों के किसान प्रतिनिधियों ने शिरकत की। कुलपति ने कहा कि पिछले वर्ष गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज्यादा रहा था, जिसके नियंत्रण के लिए अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जो चिंता का विषय है। कीट के नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशक एवं अन्य कीट मैनेजमेंट के उपायों को खोजना होगा।

सबसे बड़ा कपास उत्पादक भारत

भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। यहां दुनिया का करीब 22 फीसदी कपास पैदा होता है। बताया गया है कि करीब 60 लाख से अधिक किसान सीधे कपास की खेती से जुड़े हुए हैं। जबकि करीब पांच करोड़ लोग कपास की प्रोसेसिंग और इससे जुड़े व्यापार गतिविधियों में लगे हुए हैं। कपास देश के प्रमुख भागों में खरीफ की फसल है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मार्च से मई तक इसकी बोवनी होती है। फिलहाल भारत के कपास उत्पादक किसान इन दिनों गुलाबी सुंडी से परेशान हैं, जिसका समाधान खोजने में कृषि वैज्ञानिक जुटे हुए हैं।

यह करें किसान

कम्बोज ने कहा कि कपास की खेती से जुड़े सभी पक्षों को मिलकर गुलाबी सुंडी के मैनेजमेंट के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, तभी किसानों को इसके प्रकोप से बचाकर संभाला जा सकता है। किसान नरमे की बन्छटियों को खेत में न रखें। यदि रखी हुई है तो बिजाई से पहले इन्हें अच्छे ढंग से झाडकर उसे दूसरे स्थान पर रख दें और इनके अधखिले टिण्डों एवं सूखे कचरे को नष्ट कर दें। ताकि इन बन्छटियों से निकलने वाली गुलाबी सुंडियों को रोका जा सकें। इसके अलावा कपास की बिजाई विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित बीटी संकर किस्मों की ही करें। साथ ही 15 मई तक बिजाई पूरी करें। कीटनाशकों एवं फफूंदीनाशकों को मिलाकर छिड़काव न करें। किसान नरमे की बिजाई के बाद अपने खेत की फीरोमोट्रेप से निरंतर निगरानी रखें तथा गुलाबी सुंडी का प्रकोप नजर आने पर निकटतम कृषि विशेषज्ञ से बताए अनुसार नियंत्रण के उपाय करें।

फिर सक्रिय हुआ केवल चोर गिरोह होने लगी किसानों के खेतों से मोटरों की केवल चोरी

जागत गांव हमार, श्योपुर।

जिले के ग्रामीण क्षेत्र में केवल चोर गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है। जिसने रात्रि के दौरान खेतों पर किसानों के नलकूपों में लगी मोटरों की केवल को चोरी करना शुरू कर दिया है। इसकी बानगी बीते सप्ताह रात्रि के दौरान बड़ौदा थाना क्षेत्र के ग्राम बाजरली के हार में देखी गई है,जहां तीन किसानों के खेतों पर लगे नलकूपों की मोटर की केवल चोरी हो गई है। इस घटना से क्षेत्र के किसानों की नींद उड़ गई है। क्षेत्र के किसानों ने पुलिस के अधिकारियों से आग्रह किया है कि इस मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए केवल चोर गिरोह को दबोचा जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बड़ौदा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बाजरली के किसानों ने बताया कि बीते सप्ताह रात्रि के दौरान कैलाश मीणा, काडू बैरवा और लखन बैरवा के खेत पर लगे नलकूप की मोटर की केवल को चोर चोरी कर ले गए। जिसका पता इन किसानों को खेतों पर पहुंचने पर चला। यह पहली घटना नहीं है,इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। बड़ौदा थाना क्षेत्र ही नही अपितु जिले के अन्य थाना क्षेत्रो में भी इस तरह की घटनाएं कई बार घटित हो चुकी हैं। जिसकी शिकायते पुलिस के पास पहुंची है। हालांकि कुछ घटनाओं के आरोपियों तक तो पुलिस पहुंच गई,लेकिन ऐसी कई घटनाए भी पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद है,जिनका खुलासा नहीं हो सका है।

पुलिस को चोर गिरोह दे रहा चुनौती पुलिस के लिए खेतों में लगे नलकूपों की मोटर की केवल चोरी की घटनाएं रोकना चुनौतीपूर्ण काम है। किसानों को कहना है कि पुलिस को इस परेशानी से उन्हें निजात दिलाने के लिए चोर गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके।

चार लाख 50 हजार मीट्रिक टन गेंहू आने की उम्मीद, धान उपार्जन में हुई गड़बड़ी से लिया सबक

प्रशासन ने खराब गेंहू खरीदने पर लगाई रोक
समर्थन पर धान खरीदी में हुए फर्जीवाड़े से लिया सबक

उपार्जन केंद्र में ही साफ होगा गेहूं से कचरा किसान को देने होंगे प्रति बोरा 20 रुपए

जबलपुर। जागत गांव हमार

जिले में धान पंजीयन, खरीदी और सिकमी में हुई गड़बड़ी से जिला प्रशासन ने सबक लिया है, जिसके बाद 29 मार्च से शुरू हो रही गेहूं खरीदी के नियम और व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव उपार्जन केंन्द्र प्रभारियों को किसानों द्वारा लाए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता परखने के बाद नान एफएक्यू यानि खराब गुणवत्ता का गेहूं नहीं खरीदने कहा गया है, लेकिन इन किसानों को केंद्र से लौटाना नहीं है, बल्कि उनके गेहूं को साफ करके खरीदना है। इस सफाई में लगने वाले श्रम और मजदूर का परिश्रम किसानों को देना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों को प्रति बोरे पांच से लेकर 20 रुपए तक लेने कहा है। साथ ही किसानों से वसूली जाने वाली इस शुल्क की पावती भी उन्हें देना अनिवार्य होगा।

साफ करने की सुविधा दी जाएगी– दरअसल इस बार किसानों को उपार्जन केंद्र में ही गेहूं से कचरा साफ करने की सुविधा दी जाएगी। उपार्जन केंद्रों में सरकारी तौर पर संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि आवश्यक होने पर उपार्जन से पूर्व केंद्र में ही गेहूं से कचरा अलग किया जा सके। इधर किसानों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे कचरायुक्त गेहूं उपार्जन केंद्र में न लाएं। यदि गेहूं की खेप पहुंच जाती है तो उससे कचरा हटाने की व्यवस्था केंद्र में मौजूद रहेगी।

उपार्जन केंद्र ही तय करेंगे दाम

कलेक्टर दीपक सक्सेना ने गेहूं की सफाई का दाम तय करने की जिम्मेदारी उपार्जन केंद्र को ही दी है और कहा है कि 20 रुपए प्रति बोरे से अधिक शुल्क नहीं होना चाहिए। अभी तक किसानों का गेहूं साफ करने के लिए उपार्जन केंद्र में खुद ही मजदूर तलाशने पड़ते थे। इस वजह से कई किसानों की फसल हफ्तों डली रहती थी। इस बार बदलने नियमों को किसानों को भी गेहूं की सफाई, तुलाई और भंडारण के दौरान मौजूद रहने कहा है। कलेक्टर के मुताबिक जिन किसानों की धान उपार्जन केंद्र में आती है, वे तब तक वहां से न जाए, जब तक की उनका गेहूं तुलने से लेकर पैक लगकर टैक नहीं लग जाता है। धान खरीदी के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश किसानों ने पहले धान केंद्र में लाकर रख दी, लेकिन खरीदी और तुलाई आखिरी में हुई। धान कम होने पर अंत में पंजीयन कराने वालों को दोषी पाया गया, जबकि वे नहीं थे।

कम गेंहू आने से बढ़ेगी परेशानी

इस बार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने चार लाख 50 हजार मैट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य बनाया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इस बार जिला प्रशासन यह आंकड़ा नहीं छू पाएगा। इसकी वजह प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य कम होना है। वर्तमान में सरकार 2275 रुपय प्रति बोरा समर्थन मूल्य दे रही है। इस पर 125 रुपए का बोनस इसके बाद दिया जाएगा, लेकिन किसान 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का दाम देने की मांग कर रहे हैं। इस वजह से अधिकांश किसान,अपना गेहूं उपार्जन केंद्र में बेचने की बजाए, मंडी में बेचने का मन बना चुके हैं। इस वजह से सरकार के गोदाम में गेहूं कम आएगा, जिसका असर सरकार द्वारा गरीबों को दिए जा रहा मुफ्त गेहूं देने वाली योजना पर पड़ेगा। गेहूं की खरीदी कम होने की वजह से इस बार राशन में भी लोगों को गेहूं से ज्यादा चावल दिया जाएगा।

यह की जा रही व्यवस्था

- खराब गेहूं खरीदना नहीं, लेकिन लौटना भी नहीं है, उन्हें उपार्जन केंद्र में साफ करवाया जाएगा।
- नान एफएक्यू गेहूं का साफ करने के लिए उपार्जन केंद्र में पंखा, छन्ना और ग्रेडर मशीन लगाई जाएगी।
- किसान का गेहूं साफ करने का जो शुल्क लिया जाएगा, उसकी रसीद दी जाएगी और इसका आडिट होगा।
- केंद्र में पंचायत सचिव, पटवारी, सहकारिता विभाग के कर्मचारी की टीम गुणवत्ता जांच करेगी।

इस बार हमने धान खरीदी की प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं। नान एफएक्यू गेहूं खरीदना पर रोक लगाई गई है। गेहूं की सफाई उपार्जन केंद्र में ही होगी, इसके लिए किसान से 5 से 20 रुपए प्रति बोरे तक लिया जा सकता है। इसका रसीद भी किसानों को दी जाएगी, ताकि किसी तरह की वित्तीय अनियमितता न हो।
दीपक सक्सेना, कलेक्टर, जबलपुर

गौशाला के लिए जुटाए एक लाखः सागर। सागर जिले की खुरई नगर पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों ने अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वेतन से राशि देकर एक लाख रुपए जुटाए हैं। यह राशि हनौता गौशाला में गायों के लिए भूसा खरीदने में इस्तेमाल होगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी दुर्गेश सिंह और नोडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गौवंश के प्रति संवेदनाएं रखना हम सबका मानवीय कर्तव्य है। खुरई नगर के गणमान्य नागरिकों ने अपने-अपने स्तर से निरंतर सहयोग हनौता गौशाला को प्राप्त होता है। इसी क्रम में हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी गौवंश के प्रति प्रेम रखते हुए सहयोग करने का निर्णय लिया। पहल करते ही साथियों ने आगे आकर खुद की इच्छा से इस विशेष कार्य के लिए राशि अनुदान की है। एक लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

हार्ट, लीवर और फेफड़े के लिए भी फायदेमंद

काले आलू की खेती कर आकाश ने जिले के किसानों को दिखाई नई राह

अनिल दुबे
जागत गांव हमार, सागर।

समोसे हों या आलू के पराठे... आलू-गोभी हो या फ्रेंच फ्राइज, आलू किसी न किसी तरीके से अपनी ओर खींच ही लेता है। कभी मोटापे के डर से तो कभी ब्लड शुगर की वजह से इससे दूरी भी बनानी पड़ती है। बुंदेलखंड के सागर के किसान ने अब काले आलू की खेती कर रहा है जो कि न केवल फैट फ्री है बल्कि शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं। साथ ही इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में है, जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है। यह हार्ट, लीवर और फेफड़े के लिए भी फायदेमंद है।

मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के किसान अब पारंपरिक खेती से हटकर नई तकनीकी तथा नई फसलों के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सागर के युवा किसान दक्षिण अमेरिका में उगने वाले काले आलू की खेती कर रहे हैं। इससे सालाना पांच लाख रुपये तक कमाई हो रही है। काला आलू औषधीय फसल है, जिसके गुण और कीमत सफेद आलू के मुकाबले ज्यादा होती है। ग्राम कपूरिया के युवा आकाश चौरसिया भी एक ऐसे ही किसान हैं। आकाश ने करीब 15 साल पहले मल्टीलेयर प्राकृतिक जैविक खेती शुरू की थी। अब दूसरे किसान भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। आकाश के पास 16 एकड़ जमीन है। इसमें से एक एकड़ पर काले आलू की फसल लगी है। आकाश ने सागर जिले समेत बुंदेलखंड में किसानों को नई राह दिखाई है।

काले आलू की खेती

आकाश ने बताया कि काले आलू की खेती दक्षिण अमेरिका के एंडिज पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। अब इसकी खेती सागर में शुरू की है। प्रयोग के तौर पर पहली बार काले आलू की खेती की, जो सफल रही। तीन महीने में फसल आ जाती है। इस आलू की ऊपरी सतह काली और आंतरिक भाग गहरे बैंगनी रंग का होता है। काले आलू की खेती करने में एक एकड़ में किसान को करीब 50 हजार रुपये का खर्च आता है।

90 दिन में फसल तैयार

आकाश बताते हैं कि काले आलू की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। आकाश ने सागर जिले समेत बुंदेलखंड में पहली बार काले आलू का उत्पादन किया है। उन्होंने एक एकड़ में यह फसल लगाई थी। इसमें करीब 100 क्विंटल पैदावार हुई। वह मध्यप्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के किसानों को काला आलू उगाने की विधि सिखा रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** –9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)